दलित-मुस्लिम गठजोड़: सियासी इतिहास और मौजूदा दौर में एक मज़बूत विकल्प

विचारक: डॉ सैयद नासिर शाह

भारतीय राजनीति, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सियासत में, जातियों और धर्मों के समीकरण हमेशा से सत्ता की चाबी रहे हैं। जब भी बात शोषित, वंचित और अकलियतों (अल्पसंख्यकों) की आती है, तो 'दलित-मुस्लिम गठजोड़' एक ऐसा सियासी फॉर्मूला माना जाता है जो अगर ज़मीन पर पूरी तरह उतर जाए, तो किसी भी बड़ी राजनीतिक ताक़त को चुनौती दे सकता है।

दलित-मुस्लिम गठजोड़ का सियासी इतिहास

दलितों और मुसलमानों के बीच सियासी गठजोड़ की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं।

- **आज़ादी से पहले का दौर:** अगर ऐतिहासिक पन्नों को पलटें, तो डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने हमेशा शोषित वर्गों और अल्पसंख्यकों के हक़ की बात एक साथ की थी। जोगेंद्र नाथ मंडल (जो एक बड़े दलित नेता थे) का मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ इसी सामाजिक एकता का एक शुरुआती, हालांकि विवादास्पद, प्रयोग था।
- **कांशीराम का युग और BAMCEF:** 1980 के दशक में जब मान्यवर कांशीराम ने बहुजन राजनीति की शुरुआत की, तो उनका नारा था– *"जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।"* उन्होंने BAMCEF और DS4 के ज़रिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुसलमानों) को एक मंच पर लाने का ज़मीनी काम किया। उनका मानना था कि दलित और मुसलमान दोनों ही ब्राह्मणवादी और सामंतवादी व्यवस्था के सताए हुए हैं।
- **1993 और 2007 के सफल प्रयोग:** 1993 में कांशीराम और मुलायम सिंह यादव का गठजोड़ इसका एक बड़ा उदाहरण था। लेकिन दलित-मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा और सफल रूप 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में दिखा, जब मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस वक़्त मुसलमानों ने BSP पर भारी भरोसा जताया था।

आज के दौर में दलित-मुस्लिम (BSP) सबसे मज़बूत विकल्प क्यों है?

समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस से हो रहे मोहभंग के बीच, सियासी विश्लेषकों का मानना है कि BSP (बहुजन समाज पार्टी) के नेतृत्व में दलित-मुस्लिम गठजोड़ आज भी सबसे तार्किक (logical) और मज़बूत विकल्प साबित हो सकता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. जिताऊ गणित (The Winning Arithmetic) उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 21-22% है और मुस्लिम आबादी लगभग 19-20% है। अगर ये दोनों वोट बैंक पूरी तरह से एक साथ आ जाएं, तो यह आंकड़ा 40% को पार कर जाता है। किसी भी त्रिकोणीय (triangular) या बहुकोणीय चुनाव में 40% वोट शेयर सीधे तौर पर सत्ता की गारंटी होता है।

2. कैडर-बेस्ड और ट्रांसफ़रेबल वोट बैंक कांग्रेस और SP की तुलना में BSP की सबसे बड़ी ताक़त उसका कैडर-बेस्ड 'जाटव/दलित' वोट बैंक है।

- SP के साथ दिक्कत यह है कि ज़मीनी स्तर पर कई बार यादव और मुस्लिम हितों का टकराव होता है।
- कांग्रेस के पास अपना कोई सॉलिड कैडर वोट नहीं है; वह पूरी तरह लहर पर निर्भर है।
- दूसरी तरफ, मायावती का अपना एक फिक्स वोट बैंक है जो उनके इशारे पर ट्रांसफर होता है। अगर मुसलमान अपना वोट BSP को देते हैं, तो दलित वोट के जुड़ने से जीत की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है।

3. ज़मीनी स्तर पर सामाजिक समानता दलित और मुसलमान दोनों ही समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके से आते हैं। गांवों और कस्बों में इनके बीच कोई बड़ा ढांचागत या ज़मीनी टकराव (structural conflict) नहीं होता, जैसा कि कई बार अगड़ी या दबंग पिछड़ी जातियों के साथ देखने को मिलता है। एक जैसा दर्द और एक जैसी आर्थिक चुनौतियां इन्हें स्वाभाविक साथी (natural allies) बनाती हैं।

4. क़ानून व्यवस्था और सुरक्षा का रिकॉर्ड मुसलमानों के लिए आज के दौर में सुरक्षा (security) एक बड़ा मुद्दा है। मायावती के पिछले कार्यकालों (विशेषकर 2007-2012) को उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन 'लॉ एंड ऑर्डर' (क़ानून व्यवस्था) के लिए जाना जाता है। उस दौरान साम्प्रदायिक दंगे न के बराबर हुए थे, जो मुस्लिम समुदाय के भीतर BSP के प्रति एक भरोसे को जन्म देता है।

राह की चुनौतियां (Challenges Ahead)

हालांकि कागज़ पर यह गठजोड़ सबसे मज़बूत है, लेकिन इसे हक़ीक़त में बदलने के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं:

- **लीडरशिप की ख़ामोशी:** मायावती की हालिया राजनीतिक निष्क्रियता और सत्ताधारी दल के प्रति उनके नरम रवैये ने मुसलमानों के मन में एक शक पैदा कर दिया है कि कहीं BSP चुनाव बाद BJP से हाथ न मिला ले (जैसा 1995, 1997 और 2002 में हुआ था)।

- **नए दलित नेतृत्व का उभार:** चंद्रशेखर आज़ाद की 'आज़ाद समाज पार्टी' भी इसी दलित-मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जिससे इस गठजोड़ के वोटों का बिखराव हो सकता है।

सियासी हक़ीक़त यह है कि अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ 'वोट बैंक' या 'भाजपा को हराने की मशीन' बनने के बजाय अपनी हिस्सेदारी चाहता है, तो उसे एक ठोस राजनीतिक साथी की ज़रूरत है। दलित समुदाय से बेहतर यह साथी कोई और नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पास वह बुनियादी ढांचा और कोर वोट बैंक मौजूद है जो इस सपने को साकार कर सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि BSP की लीडरशिप मुसलमानों का वह खोया हुआ भरोसा दोबारा जीत सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में जज़्बात से ज़्यादा ज़मीनी हक़ीक़त (ground reality) मायने रखती है। जब बात दलित-मुस्लिम गठजोड़ की आती है, तो मायावती की BSP और चंद्रशेखर आज़ाद की ASP के दरमियान फ़र्क़ को समझना बेहद ज़रूरी है। सियासी हक़ीक़त यह है कि BSP आज भी एक मज़बूत क़िला है, जबकि ASP अभी अपनी बुनियाद ढूंढ रही है।

यहाँ इस बात का तफ़सीली तज्ज़िया (analysis) है कि BSP क्यों बेहतर विकल्प है और ASP से मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है:

मायावती और BSP की असल मज़बूती

BSP सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक पिछले 40 सालों में बना हुआ मूवमेंट है। इसकी मज़बूती हवा में नहीं, ज़मीन पर है।

* **सॉलिड कोर वोट बैंक (Solid Core Vote Bank):** BSP के पास जाटव समाज का एक ठोस वोट बैंक (क़रीब 12-14%) है। यह वोट बैंक किसी भी हालात में मायावती का साथ नहीं छोड़ता और उनके एक इशारे पर ट्रांसफ़र होता है।

* **ज़मीनी संगठन (Cadre):** UP के 75 ज़िलों और गाँव-गाँव में बूथ सतह पर BSP का कैडर सिस्टम मौजूद है। चुनाव लड़ने के लिए जो मशीनरी चाहिए, वो BSP के पास पहले से तैयार है।

* **प्रशासन का तजुर्बा:** मायावती चार बार UP की मुख्यमंत्री रही हैं। उनका 'लॉ एंड ऑर्डर' का रिकॉर्ड और ब्यूरोक्रेसी (अफ़सरशाही) पर पकड़ बेमिसाल मानी जाती है।

आज़ाद समाज पार्टी (ASP) की कमज़ोरियां

चंद्रशेखर आज़ाद के पास जोश ज़रूर है, लेकिन सियासत सिर्फ जोश से नहीं चलती। ASP के साथ कई अहम कमज़ोरियां जुड़ी हैं।

* **संगठन की कमी:** ASP के पास यूथ और सोशल मीडिया का शोर ज़रूर है, लेकिन बूथ-लेवल पर चुनाव लड़ने और जीतने वाली ज़मीनी मशीनरी बिल्कुल ग़ायब है।

* **वोट ट्रांसफ़र की नाकामी:** चंद्रशेखर अभी तक कोर दलित वोट (ख़ास कर बुज़ुर्ग और महिलाएं) को मायावती से तोड़ कर अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हुए हैं।

* **जज़्बाती सियासत:** नगीना की एक सीट जीतना और पूरे UP में 403 सीट्स पर मुक़ाबला करना, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। ASP अभी स्टेट-वाइड सियासी ताक़त नहीं बन पाई है।

मुसलमान वोटर को BSP के साथ क्या फायदा है?

मुसलमानों के लिए BSP एक प्रैक्टिकल और नतीजा-खेज़ (result-oriented) विकल्प है।

* **जीत का गारंटी फॉर्मूला:** मुस्लिम (20%) और BSP का कोर दलित (15%) मिलकर 35% का आंकड़ा पार करते हैं। यह कॉम्बिनेशन UP में सरकार बनाने के लिए सबसे आसान और कारगर गणित (arithmetic) है।

* **दंगे-मुक्त शासन:** मायावती के कार्यकाल में UP में दंगे नहीं हुए। मुसलमानों के लिए सबसे पहली ज़रूरत जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ (safety) है, जो BSP का ट्रैक रिकॉर्ड गारंटी करता है।

* **सियासी हिस्सेदारी:** BSP टिकट बंटवारे में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हमेशा बड़ा शेयर (टिकट) देती है, जिससे क़ौम की लेजिस्लेटिव रिप्रेज़ेंटेशन बढ़ती है।

मुसलमानों को ASP के साथ जाने में क्या नुकसान है?

मुसलमान अगर जज़्बात में आकर ASP की तरफ़ जाते हैं, तो इसका उन्हें भारी सियासी ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है।

* **वोट का बिखराव (Vote Division):** ASP के पास खुद का इतना सॉलिड वोट नहीं है कि वो अकेले UP में सीट्स निकाल सके। मुसलमान वोट ASP को जाने से वोट सिर्फ बंटेगी, जिसका सीधा फायदा BJP को होगा। इन्हें "वोट-कटवा" का टैग मिलने का ख़तरा है।

* **सड़क बनाम सत्ता (Sadak vs Satta):** चंद्रशेखर सड़क पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी को पॉलिसी और प्रोटेक्शन देने के लिए विधानसभा में पावर चाहिए। सड़क की सियासत से क़ौम की मआशी और तालीमी (economic and educational) तरक़्क़ी नहीं होती।

* **तजुर्बे का फुक्दान:** एक नई और तजुर्बा-हीन पार्टी पर अपना पूरा भरोसा डाल कर मुसलमान अपनी बची-खुची सियासी ताक़त भी ज़ाया (waste) कर सकते हैं, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो जाएगी।

निष्कर्ष

सियासी इतिहास और मौजूदा हालात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद निम्नलिखित बातें साफ़ हो जाती हैं:

जज़्बात बनाम हक़ीक़त: सियासत महज़ जोश से नहीं, बल्कि ज़मीनी मशीनरी और तजुर्बे से जीती जाती है। BSP के पास 40 साल का कैडर और सत्ता का तजुर्बा है, जबकि ASP अभी भी अपनी ज़मीनी बुनियाद तलाश रही है।

वोट के बिखराव का ख़तरा: अगर मुसलमान ASP के पीछे जाते हैं, तो उनका वोट सिर्फ बंटेगा और वह बिना किसी सत्ता हासिल किए 'वोट-कटवा' बनकर रह जाएंगे। इसका सीधा सियासी फायदा BJP को होगा।

सुरक्षा और हिस्सेदारी की गारंटी: मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत जान-ओ-माल का तहफ्फुज़ (सुरक्षा) और सियासी हिस्सेदारी है। BSP का 'मुस्लिम (20%) + कोर दलित (15%)' का गणित ही यूपी में सरकार बनाने और दंगा-मुक्त शासन देने का सबसे कामयाब फॉर्मूला है।

आगे का रास्ता: यह गठजोड़ तभी ज़मीन पर उतरेगा जब मुसलमान अपनी बार्गेनिंग पावर को ज़ाया करने के बजाय एक ठोस पार्टी का साथ दें, और बदले में BSP नेतृत्व मुसलमानों के बीच पैदा हुए शक को दूर कर उनका पूरा भरोसा जीते।